The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 6 | June 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

भारत के राजनीतिक दलों में जातियों की भूमिका (नागौर जिले के सन्दर्भ में अध्ययन)

मोहम्मद जावेद खान

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग निर्वान विश्वविधालय, राजस्थान

डॉ0 रितेश मिश्रा

प्रोफेसर, निर्वाण विश्वविधालय, जयपुर ,राजस्थान

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords:

Non-Performing Assets (NPAs), Stock Price Volatility, Private Sector Banks, Panel Data Methodology, Macroeconomic Factors

ABSTRACT

राजस्थान के राजनीतिक दलों में जातियों की भूमिका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर नागौर जिले में नागौर जिला राजस्थान का एक प्रमुख जिला है, जो अपनी जातिगत राजनीति के लिए जाना जाता है। नागौर जिले में जाट, राजपूत, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम जैसी कई जातियों के लोग रहते हैं। इन जातियों की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएँ हैं, जो जिले की राजनीति को आकार देते हैं। नागौर जिले में जातिगत राजनीति एक महत्वपूर्ण कारक है। जिले में विभिन्न जातियों के लोगों ने राजनीतिक दल बनाए हैं और चुनावों में भाग लिया है। जाट समुदाय नागौर जिले का सबसे बड़ा जाति समूह है, और वे राजनीति में बहुत प्रभावशाली हैं। नागौर जिले की राजनीति में परिवारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जिले में कई प्रमुख राजनीतिक परिवार हैं, जो पीढ़ियों से राजनीति में सक्रिय हैं। इनमें से कुछ प्रमुख परिवार बेनीवाल परिवार, मिर्धा परिवार हैं। इस प्रकार, राजस्थान के राजनीतिक दलों में नागौर जिले में जातियों और परिवारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जिले की राजनीति को समझने के लिए, जाति और परिवार के कारकों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

परिचय

भारत के राजनैतिक दलों में जातियों की भूमिका एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा रही है और इसका प्रभाव राजनीति पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जातियों का प्रभाव चुनावों में उम्मीदवारों के चयन, वोट बैंक की राजनीति, और सरकार की नीतियों पर भी देखा जा सकता है। विभिन्न जातियाँ जैसे जाट, राजपूत, और अन्य पिछड़ी जातियाँ (OBC) राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक मानी जाती हैं। इस प्रकार, जातियों की भूमिका न केवल सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है, बल्कि राजनीतिक दलों की रणनीतियों और नीतियों को भी निर्धारित करती है। यह एक जटिल और बहुआयामी विषय है, जो भारतीय राजनीति की गहरी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। जातियों की भूमिका भारतीय राजनीति में एक गहरी और व्यापक प्रभाव डालती है। यह प्रभाव न केवल चुनावों में बल्कि सरकार की नीतियों और निर्णयों में भी देखा जा सकता है।

चुनावों में जातियों का प्रभाव: चुनावों के दौरान, राजनीतिक दल अक्सर जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अधिकतम वोट प्राप्त कर सकें, दल अक्सर उन जातियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जो उस क्षेत्र में प्रभावशाली होती हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, जातिगत समीकरण चुनावी परिणामों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं।

वोट बैंक की राजनीति: जातियों का प्रभाव वोट बैंक की राजनीति में भी देखा जा सकता है। राजनीतिक दल अक्सर विशेष जातियों को लुभाने के लिए नीतियाँ और योजनाएँ बनाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उन जातियों के वोट प्राप्त कर सकें, दल अक्सर उन जातियों के नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ गठजोड़ करते हैं।

सरकारी नीतियों पर प्रभाव: जातियों का प्रभाव सरकार की नीतियों और निर्णयों पर भी देखा जा सकता है। विभिन्न जातियों के नेताओं और संगठनों का दबाव सरकार पर होता है कि वे उनकी मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने वोट बैंक को बनाए रख सकें, सरकार अक्सर उन जातियों के लिए विशेष योजनाएँ और नीतियाँ बनाती है।

सामाजिक संरचना पर प्रभाव: जातियों का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करता है। जातिगत समीकरण समाज में सत्ता और प्रभाव के वितरण को निर्धारित करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा कर सकें, विभिन्न जातियाँ राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ करती हैं।

इस प्रकार, जातियों की भूमिका भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है। यह न केवल चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है, बल्कि सरकार की नीतियों और समाज की संरचना को भी निर्धारित करती है। जातियों का प्रभाव भारतीय राजनीति की गहरी समझ के लिए महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

नागौर जिले में जातियों की भूमिका भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है। नागौर, राजस्थान का एक प्रमुख जिला है, जहाँ विभिन्न जातियों का प्रभाव राजनीति पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

चुनावों में जातियों का प्रभाव: नागौर जिले में चुनावों के दौरान, राजनीतिक दल अक्सर जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अधिकतम वोट प्राप्त कर सकें, दल अक्सर उन जातियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जो उस क्षेत्र में प्रभावशाली होती हैं.

वोट बैंक की राजनीति: नागौर जिले में जातियों का प्रभाव वोट बैंक की राजनीति में भी देखा जा सकता है। राजनीतिक दल अक्सर विशेष जातियों को लुभाने के लिए नीतियाँ और योजनाएँ बनाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उन जातियों के वोट प्राप्त कर सकें, दल अक्सर उन जातियों के नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ गठजोड़ करते हैं.

सरकारी नीतियों पर प्रभाव: नागौर जिले में जातियों का प्रभाव सरकार की नीतियों और निर्णयों पर भी देखा जा सकता है। विभिन्न जातियों के नेताओं और संगठनों का दबाव सरकार पर होता है कि वे उनकी मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करें ।

इस प्रकार, नागौर जिले में जातियों की भूमिका न केवल सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है, बल्कि राजनीतिक दलों की रणनीतियों और नीतियों को भी निर्धारित करती है। यह एक जटिल और बहुआयामी विषय है, जो भारतीय राजनीति की गहरी समझ के लिए महत्वपूर्ण है।

नागौर जिले में जातिगत राजनीति–

नागौर जिले में जातिगत राजनीति एक महत्वपूर्ण कारक है। जिले में विभिन्न जातियों के लोगों ने राजनीतिक दल बनाए हैं और चुनावों में भाग लिया है। जाट समुदाय नागौर जिले का सबसे बड़ा जाति समूह है, और वे राजनीति में बहुत प्रभावशाली हैं।

नागौर जिले में राजनीतिक दलों की भूमिका–

नागौर जिले में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जिले में कई राजनीतिक दल हैं, जिन्हें जाति के आधार पर समर्थन मिलता है। नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आर–एल–पी–) बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जैसे राजनीतिक दल सक्रिय हैं।

राजनीतिक प्रक्रिया में जाति की गतिशीलता–

राजनीतिक प्रक्रिया में जाति की सक्रियता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो भारतीय राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जाति की सक्रियता के कारण, राजनीतिक दल जाति के आधार पर मतदान को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है ।

जाति और चुनाव– चुनावी प्रक्रिया में जाति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल जाति के आधार पर उम्मीदवारों के चयन और मतदान को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

जाति के आधार पर संरक्षण– भारतीय संविधान में जाति के आधार पर संरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है।

जाति और राजनीतिक स्थिति– राजनीतिक पदों के लिए जाति की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल जाति के आधार पर राजनीतिक पदों का वितरण करते हैं।

राजनीतिक दलों में जातियों की भूमिका का मूल्यांकन–

राजनीतिक दलों में जातियों की भूमिका का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि जाति एक महत्वपूर्ण कारक है जो राजनीतिक दलों की रणनीतियों और नीतियों को प्रभावित करती है।

जातियों की भूमिका के सकारात्मक पहलू हैं–

जाति प्रतिनिधित्व– जातियों की भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक प्रक्रिया में विभिन्न जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो।

जाति सामाजिक न्याय – जातियों की भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न जातियों के लोगों को सामाजिक न्याय मिले।

जातियों की भूमिका के नकारात्मक पहलू –

जाति विभाजन– जातियों की भूमिका कभी–कभी जाति विभाजन को बढ़ावा देती है, जो सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाती है।

जाति की राजनीति– जातियों की भूमिका कभी–कभी जाति की राजनीति को जन्म देती है, जो राजनीतिक दलों की नीतियों और रणनीतियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

प्राचीन भारत में जाति और राजनीति–

प्राचीन भारत में जाति और राजनीति के बीच गहरा संबंध था। प्राचीन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को निर्धारित किया।

प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था में चार मुख्य श्रेणियाँ थीं–

1– ब्राह्मण– ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च माना जाता था। वे पुजारी और शिक्षक के रूप में काम करते थे।

2– क्षत्रिय– क्षत्रिय वर्ग को योद्धा और शासक माना जाता था। वे राजा और सेनापति के रूप में काम करते थे।

3– वैश्य– वैश्य वर्ग को व्यापारी और किसान माना जाता था। वे व्यापार और कृषि के क्षेत्र में काम करते थे।

4– शूद्र– शूद्र वर्ग को सबसे नीच माना जाता था। वे नौकर और मजदूर के रूप में काम करते थे।

प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था का राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। राजाओं और शासकों का चयन अक्सर जाति के आधार पर किया जाता था। क्षत्रिय वर्ग के लोगों को राजा और शासक माना जाता था जबकि ब्राह्मण वर्ग के लोगों को पुजारी और शिक्षक माना जाता था। हालाँकि, प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था ने कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ भी पैदा कीं। जाति व्यवस्था के कारण, व्यक्तियों को अपनी जाति के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों और सीमाओं का सामना करना पड़ता था।

इस प्रकार, प्राचीन भारत में जाति और राजनीति के बीच गहरा संबंध था, जो व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को निर्धारित करता था।

राजनीतिक दलों में जाति की भूमिका का मूल्यांकन–

यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू जाति है। जिसे भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक कारक माना जा सकता है। जहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के तहत जाति ने देश की राजनीति में कुछ विकास किया है, वहीं जातिवाद ने देश की राजनीति और राजनीतिक दलों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसलिए राजनीति और राजनीतिक दलों में जाति की भूमिका का मूल्यांकन सकारात्मक और नकारात्मक भूमिकाओं के तहत किया गया है।

सकारात्मक भूमिका–

वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अस्तित्व और राजनीतिक दलों के माध्यम से सभी जातियों और समुदायों में राजनीति के प्रति स्वाभाविक रुचि विकसित हुई है। अंगड़ी जातियों की तरह पिछड़ी जातियाँ भी राजनीतिक दलों के माध्यम से देश के शासन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। जातियों के राजनीतिकरण का एक सकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि पिछड़ी और निम्न सामाजिक स्थिति वाली जातियों की सामाजिक स्थिति में बदलाव आया और सभी जातियों में समानता की भावना विकसित हुई। राजनीतिक दलों और राजनीति में जातियों की प्रभावशाली भूमिका के कारण सभी जातियों वर्गों तथा समुदायों के लोग अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं।

नकारात्मक भूमिका–

जातियों के राजनीतिकरण के कारण उपरोक्त घटनाक्रम तो हुए हैं, लेकिन यह भी सच है कि राजनीति में जाति के नकारात्मक रूप यानी जातिवाद का विस्तार राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों और स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया गया है। इसके निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं। जाति आधारित राजनीति ने सामाजिक असंतोष को जन्म दिया है और यह सामाजिक असंतोष आरक्षण के लिए विभिन्न जातियों द्वारा चलाए जा रहे तनाव और हिंसक आंदोलनों के रूप में सामने आ रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा जाति आधारित राजनीति के कारण देश के विकास की गति भी प्रभावित हुई है और विकास की गति धीमी हो गई है। राजनीतिक दलों और जाति संगठनों के बीच गठजोड़ के कारण सभी नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास समान रूप से नहीं हो पाता। राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों और स्वार्थों की पूर्ति के लिए जाति नेताओं और जाति संगठनों के साथ किए गए राजनीतिक गठजोड़ के परिणामस्वरूप आम लोगों को उचित और योग्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता।

निष्कर्ष –

जातियों के राजनीतिकरण से यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि जातिवाद की महामारी ने भारतीय राजनीति और राजनीतिक दलों को अपनी चपेट में ले लिया है। हर राजनीतिक विचारधारा की तरह जातिवाद के समर्थक भी इसे सामाजिक परिवर्तन के एक संपूर्ण दर्शन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर जाति की अपनी सीमाएँ और विशेषताएँ हैं। इन सीमाओं और विशेषताओं का विश्लेषण करने पर जाति के कारण राजनीति में उत्पन्न होने वाली समस्याएँ स्वतः ही सामने आ जाएँगी।

जाति के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक सत्ता के लिए जाति की पारंपरिक वैधता समाप्त होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना को अपनी चुनावी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। जब शासन करने का अधिकार कुछ जाति समूहों तक सीमित था, तो सत्तारूढ़ दल बनने के लिए जाति के आंकड़े एकत्र करना अनावश्यक था। जैसे ही पारंपरिक प्रतिबंध समाप्त हुए, राजनीतिक दलों ने सत्ता हासिल करने के लिए जाति को एक इकाई के रूप में पेश किया। क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि इकाइयों की जगह राजपूत, रेड्डी, लिंगायत, यादव, कुर्मी आदि जातियाँ आ गईं। सत्ता पर उनका दावा भी जाति पर टिका है। यह मनुवाद का परित्याग नहीं बल्कि मनुवाद का नवीनीकरण है।

कठिनाई यह है कि जातियों के अपने–अपने हितों के अनुसार ध्रुवीकरण के बाद भी कोई भी जाति समूह दूसरों की चुनौतियों को खत्म नहीं कर पाता। इस ध्रुवीकरण से बाहर खड़ी जातियां अपना ध्रुवीकरण खुद करती हैं। उदाहरण के लिए पाटीदारों का ध्रुवीकरण ब्राह्मणों और बनियों को बाहर करने के लिए हुआ। पाटीदारों के सत्ता में आते ही क्षत्रियों का ध्रुवीकरण शुरू हो गया। राजपूतों ने कोली, भील, बारिया आदि जातियों पर क्षत्रिय का ठप्पा लगाकर उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। ऐसे उदाहरण हर राज्य में देखे जा सकते हैं जैसे गुजरात में खाम क्षत्रिय, हरिजन, अहीर, मुस्लिम और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अजगर अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत।

संख्या की दृष्टि से शक्तिशाली जातियों के बीच एकता से मिलने वाली राजनीतिक शक्ति सत्ता के लालच को जमा करके आंतरिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। जाति के सक्षम नेता अपने–अपने समूह बनाकर राजनीतिक दलों के माध्यम से सत्ता में सर्वोच्च बनने की कोशिश करते हैं। आंतरिक प्रतिस्पर्धा उन्हें अपनी जाति की सीमाओं से बाहर जाकर दूसरी जातियों के साथ गठबंधन करने के लिए प्रेरित करती है। जाति रिश्तेदारी के आधार पर सत्ता हासिल करती है।

अतः यह स्पष्ट है कि जाति और राजनीति के बीच अंतर्क्रिया का परिणाम यह हुआ है कि जाति का राजनीतिकरण हो गया है। शोधकर्ता द्वारा अनुभवियों तथा तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं –

1– राजनीति और जाति के बीच संबंध गतिशील है।

2– जाति का महत्व और भूमिका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर उतनी नहीं है जितनी स्थानीय और राज्य की राजनीति पर है।

3– चुनाव के समय जाति समुदाय प्रस्ताव पारित करके और राजनीतिक नेताओं और दलों को अपना जाति–आधारित समर्थन घोषित करके अपने हितों को व्यक्त करते हैं।

4– औद्योगीकरण, शहरीकरण, शिक्षा और आधुनिकीकरण ने जातियों को समाप्त नहीं किया है बल्कि उनके बीच एकीकरण की प्रवृत्ति को मजबूत किया है और उनकी राजनीतिक भूमिका को बढ़ाया है।

5– 19वीं शताब्दी में ही जाति समुदायों का राजनीति की ओर झुकाव हुआ जबकि ब्रिटिश शासन ने भारत में एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी।

सुझाव–

1– राजनीतिक दलों को अपने दल में उच्च व्यक्तित्व वाले जनप्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए ताकि आम जनता के विचारों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

2– हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए ताकि चुनाव के दौरान तनाव और जातिवाद पैदा न हो, बल्कि आम जनता में राजनीतिक जागरूकता विकसित की जानी चाहिए।

3– राजनीतिक दलों में सभी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, न कि केवल कुछ सक्रिय जातियों को।

4– राजनीतिक दलों को केवल योग्य उम्मीदवारों को ही नामांकित करना चाहिए, न कि केवल संपन्न जाति के नेताओं को।

5– राजनीतिक दलों को संविधान का सम्मान करना चाहिए और केवल समर्थन प्राप्त करने के लिए विभिन्न जातियों द्वारा चलाए जा रहे आरक्षण आंदोलनों का समर्थन नहीं करना चाहिए।

6– राजनीतिक दलों को अपने घोषणापत्रों और नीतियों में आरक्षण के मुद्दे को शामिल नहीं करना चाहिए।

7– यदि किसी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में जोड़ा जाना है, तो आम सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।

8– सरकार को आम सहमति के माध्यम से आरक्षण के मुद्दे को संभालना चाहिए और हर पांचवें वर्ष आरक्षण के मुद्दे को जारी रखने या न रखने के मुद्दे पर विचार करना चाहिए।

सन्दर्भ–

1 श्रीधर केतकर, बी द हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इण्डिया, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1979, पृ– सं– 30 ।

2– मीना राठौड़, भारत में राजनैतिक दल, आर–बी–एस– पब्लिशर्स, जयपुर, 2003, पृ–सं– 253 ।

3 रजनी कोठारी, साम्प्रदायिकता और भारतीय राजनीति रेनबो पब्लिशर्स लिमिटेड, दिल्ली पू–सं– 113

चिरानिया बी–एल– 1995 जाति विहीन समाजष बार पी पी एच जयपुर ।

4 डॉ– जयप्रकाश शर्मा भारतीय राजनैतिक व्यवस्थाष राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ ।

5 नागौर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास डॉ. मोहनलाल गुप्ता ।

6 नागौर (जिलेवार सांस्कृतिक सर्वेक्षण) जवाहर कला केन्द्र जयपुर ।

7 नागौर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक वैभव महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर ।